कार्यकारी आदेश 2026-01
नई सुरक्षित व्यवस्था को गति देने के लिए कार्यकारी आदेश
इलिनॉय में परमाणु ऊर्जा उत्पादन

जबकि, लोक अधिनियम 102-0662, जिसे जलवायु और समान रोजगार अधिनियम (CEJA) के रूप में जाना जाता है, इलिनॉय राज्य का लक्ष्य 2050 तक पूरे राज्य में 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था प्राप्त करना निर्धारित करता है; और,

जबकि, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य ने मौजूदा परमाणु संयंत्रों के समर्थन; मजबूत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के विकास; और नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक की स्थापना, और अन्य कई उपायों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को कई तरीकों से प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मेगावाट की नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास हुआ है; और,

जबकि, स्वच्छ और विश्वसनीय ग्रिड सामर्थ्य अधिनियम (CRGA), जिसे हाल ही में कानून के रूप में पारित किया गया है, राज्य एजेंसियों को स्वच्छ ऊर्जा, संसाधन पर्याप्तता और सामर्थ्य लक्ष्यों के प्रति प्रतिक्रिया देने की चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त टूल्स प्रदान करता है; और,

जबकि, CRGA में निर्धारित टूल्स में नए परमाणु संयंत्रों के विकास पर प्रतिबंध हटाने, के साथ-साथ एकीकृत संसाधन योजना (IRP) प्रक्रिया स्थापित करना शामिल है जो राज्य एजेंसियों को पहचान की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की मात्रा और प्रकार तथा उन संसाधनों की खरीद की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की अनुमति देगा; और,

जबकि, संयुक्त एजेंसी सीईजेए द्वारा निर्देशित संसाधन पर्याप्तता अध्ययन (आरए स्टडी) अध्ययन में पाया गया कि पीजेएम इंटरकनेक्शन (PJM) और मिडकॉन्टिनेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर (एमआईएसओ) - इलिनॉय में क्षेत्रीय ट्रांसमिशन संगठन (RTOs) जो क्षमता बाजारों को डिजाइन और प्रशासित करते हैं - को आने वाले दशक में क्षमता की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण लोड वृद्धि के अनुमान हैं जो पिछले बीस वर्षों में पीजेएम या एमआईएसओ के बाजारों में देखे गए स्तरों से काफी ऊपर हैं, जब तक कि अतिरिक्त नए क्षमता संसाधनों का विकास नहीं किया जाता है; और,

जबकि, आरए अध्ययन में आरटीओ इंटरकनेक्शन कतारों को नई पीढ़ी को ऑनलाइन लाने में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक बताया गया है; और,

जबकि, आरए अध्ययन में पाया गया कि पीजेएम और एमआईएसओ में नवीनतम नीलामी में प्रत्येक ने रिकॉर्ड उच्च क्षमता मूल्य निर्धारित किए, जो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता और उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती लागत का संकेत देते हैं; और,

जबकि, इलिनॉय विश्व की पहली नियंत्रित, स्व-पोषित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया का जन्मस्थान है, जिसे 2 दिसंबर, 1942 को एनरिको फर्मी और शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा संचालित किया गया था; और,

जबकि, इलिनॉय किसी भी अन्य राज्य की तुलना में परमाणु ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पन्न करता है, जो देश के कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक-आठवां हिस्सा है और 2024 में, इलिनॉय के छह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, जिनमें कुल ग्यारह रिएक्टर हैं, ने राज्य के कुल बिजली उत्पादन का 53% उत्पादन किया; और,

जबकि, परमाणु ऊर्जा उत्पादन विश्वसनीय, कार्बन-मुक्त बिजली प्रदान करता है जिसमें संसाधन पर्याप्तता के गुण होते हैं जो इलिनॉय राज्य के बढ़ते बिजली की मांग को पूरा करने और राज्य के पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए लाभकारी हैं; और,

चूंकि, इलिनॉय में 40 वर्षों में पहली नई परमाणु व्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य में नई परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, मौजूदा परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार और मौजूदा परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को समझना आवश्यक है; और,

जबकि, इस समझ को विकसित करने से इलिनॉय के निवासियों के लिए समय के साथ न्यूनतम कुल लागत पर पर्याप्त, विश्वसनीय, किफायती, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विद्युत सेवा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी; और,

जबकि , पूछताछ सूचना (NOI) एक महत्वपूर्ण टूल्स है जो न केवल विश्लेषणात्मक जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है बल्कि असीमित संख्या में पक्षों से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हुए, चल रही एकीकृत संसाधन योजना (IRP) प्रक्रियाओं में जानकारी के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति देता है, और सभी इच्छुक हितधारकों के साथ निरंतर चर्चा की अनुमति देता है; और,

जबकि , इलिनॉय वाणिज्य आयोग (ICC) के पास आरटीओ सदस्यता की लागत और लाभों का निर्धारण, चरम मौसम की घटनाओं के लिए इलिनॉय की उपयोगिताओं की तैयारी, इलिनॉय की अर्थव्यवस्था के लाभकारी विद्युतीकरण के लिए सफल दृष्टिकोण, ऊर्जा की वहनीयता सुनिश्चित करना और इलिनॉय के ऊर्जा बाजारों के भीतर ऐसी रणनीतियों को आगे बढ़ाना जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इलिनॉय ऊर्जा नीति को प्रभावी ढंग से आकार देने और संचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी की आलोचनात्मक जांच करने के लिए जांच नोटिस का उपयोग करने का एक व्यापक इतिहास है; और,

जबकि , इलिनॉय वाणिज्य आयोग और इलिनोइस विद्युत एजेंसी (IPA) के पास ऊर्जा नीति में पर्याप्त विशेषज्ञता है, जो उन्हें जांच नोटिस का उपयोग करके वर्तमान और भविष्य के इलिनॉय ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक नीतियों के साथ-साथ अपने निष्कर्षों का मूल्यांकन और प्रस्तुत करने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है, जिसमें इलिनॉय के निवासियों के लिए समय के साथ न्यूनतम कुल लागत पर पर्याप्त, विश्वसनीय, किफायती, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विद्युत सेवा सुनिश्चित करने के लिए नई परमाणु ऊर्जा की भूमिका भी शामिल है;

अतः, मैं, जेबी प्रित्जकर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान और इलिनॉय राज्य के कानूनों द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के आधार पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुरोध करता हूँ:

I. इलिनॉय पावर एजेंसी और इलिनॉय कॉमर्स कमीशन, इस कार्यकारी आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर, और आवश्यकतानुसार अन्य राज्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने के बाद, इलिनॉय के आवासीय उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली नई परमाणु ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं के संभावित डेवलपर्स को एनओआई जारी करें, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

a. प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों की नाममात्र क्षमता का मेगावाट में आकार और प्रौद्योगिकी प्रकार, जिसमें लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकी की तैनाती भी शामिल है;

b. प्रत्येक प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के लिए वित्तपोषण विकल्प और रूपरेखा, जिसमें अनुरोधित स्वच्छ ऊर्जा क्रेडिट या अन्य सहायक राज्य नीति शामिल है, और क्या प्रस्तावित परमाणु संयंत्र किसी अन्य संयंत्र के साथ सह-स्थित है या सीधे संयंत्र को बिजली बेच रहा है;
c. प्रत्येक परमाणु संयंत्र के लिए संभावित स्थल, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई संयंत्र इक्विटी निवेश समुदाय के लिए पात्र होगा;
d. वित्तीय जोखिम आवंटन ढांचा;
e. ग्रिड अंतर्संबंध की उपलब्धता;
f. परमाणु संयंत्र को चालू करने की अनुमानित लागत और समयसीमा;
g. क्या यह परियोजना इलिनॉय की विशिष्ट संसाधन पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है;
h. क्या यह परियोजना इलिनॉय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है?
i. प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के लिए पानी की आवश्यकता और निर्दिष्ट स्थानों के लिए उपलब्ध विकल्प;
j. कार्यबल संबंधी आवश्यकताएं, जिनमें कार्यबल विकास प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं, डेवलपर द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम या कार्यबल या श्रम संगठनों के साथ साझेदारी शामिल हैं;
k. परमाणु संयंत्र स्थापित करने की संभावित जगहों से संबंधित समुदायों के साथ कोई भी संपर्क और परमाणु संयंत्र स्थापित करने की संभावित जगहों को होने वाले किसी भी अपेक्षित या प्रस्तावित लाभ;
l. ईंधन भरने की लाइफ साइकिल योजनाएँ, जिनमें ईंधन की जरूरतों को पूरा करने और अपशिष्ट निपटान को सुरक्षित रूप से संभालने की योजनाएँ शामिल हैं;
m. क्या एनओआई प्रतिक्रिया में शामिल किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए नए कानून की आवश्यकता हो सकती है; और
n. आईपीए और आईसीसी द्वारा इलिनॉय की विशिष्ट संसाधन पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अन्य जानकारी;

II. यह कि आईपीए और आईसीसी में एनओआई के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि समान जानकारी चाहने वाली मौजूदा साइटों के संभावित विस्तार या उन्नयन को, जैसा उचित हो, ऊपर आइटम 'ए-एन' में संबोधित किया जा सके;

III. इलिनॉय विश्वविद्यालय अपने ग्रेंजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परमाणु, प्लाज्मा और रेडियोलॉजिकल डिवीजन से विषय वस्तु विशेषज्ञता प्रदान करे ताकि आईपीए और आईसीसी का समर्थन किया जा सके;

IV. आईपीए को आगामी 12 से 36 महीनों में एजेंसी द्वारा अनुभव की जाने वाली स्टाफिंग और सलाहकार आवश्यकताओं और क्षमता पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन विकास, मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार, या मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक पैमाना और विशेषज्ञता हो, जिसमें संभावित रूप से नई भूमिकाओं की स्थापना या नई मुख्य दक्षताओं का विकास शामिल है;

V. आईसीसी, आवश्यकतानुसार अन्य राज्य एजेंसियों से परामर्श करने के बाद, एक नया परमाणु संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक समुदायों से जानकारी मांगने के लिए दूसरा सूचना आमंत्रण (एनओआई) जारी करे ताकि ऐसे संयंत्र की मेजबानी के लिए प्रबल क्षमता वाले कम से कम एक स्थल की पहचान की जा सके; ऐसे एनओआई में भूमि की उपलब्धता, जल की लागत और उपलब्धता, स्थानीय आर्थिक विकास से संबंधित विशेषताएं, समुदाय के सदस्यों और प्रमुख हितधारकों का समर्थन, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले बिजली संयंत्रों सहित अंतर्संबंधी

अवसंरचना की उपलब्धता और आईसीसी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य जानकारी मांगी जा सकती है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी।

VI. उपर्युक्त वर्णित सूचना-पत्रों से प्राप्त जानकारी को सीआरजीए के तहत आवश्यक आईआरपी प्रक्रिया के लिए विचार-विमर्श में शामिल किया जाएगा; हालांकि, सूचना-पत्रों के माध्यम से विकसित जानकारी को किसी विशेष आईआरपी परिणाम को निर्धारित करने वाला नहीं माना जाएगा;

VII. आईपीए, आईसीसी, वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग (डीसीईओ), पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (आईईपीए), प्राकृतिक संसाधन विभाग (आईडीएनआर), आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी-गृह सुरक्षा कार्यालय (आईईएमए-ओएचएस), श्रम विभाग (आईडीओएल), और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियां, इलिनॉय विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ मिलकर, एक अंतर-एजेंसी कार्य समूह का गठन करें, जो संभावित विकासकर्ताओं को सूचना अधिसूचना (एनओआई) जारी करने के 120 दिनों के भीतर राज्यपाल (गवर्नर) कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें कम से कम दो गीगावाट क्षमता वाले नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन या उन्नयन के विकास से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया जाए, जिसका निर्माण 2033 तक शुरू होना है।

a. नए परमाणु संयंत्रों को प्रभावित करने वाले मौजूदा वैधानिक और नियामक प्राधिकरण की समीक्षा;
b. किसी नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा, पर्यावरण, अंतर्संबंध या अन्य नियमों के संबंध में कोई भी सिफारिशें;
c. सीआरजीए के प्रावधानों के अलावा, किसी नए परमाणु संयंत्र को समायोजित करने के लिए राज्य को जिन खरीद प्रक्रियाओं को अपनाना या संशोधित करना होगा; और
d. नए परमाणु संयंत्रों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के तरीके, जिनमें ग्राहकों की वहनीयता और सुरक्षा पर विचार करना; राज्य और उपयोगिता ग्राहकों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक जोखिम; अंतर्संबंध संबंधी मुद्दे; और एजेंसियों द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मुद्दे शामिल हैं।

इस जानकारी को विकसित करने में, राज्य एजेंसियां आवश्यकतानुसार बाहरी समूहों से परामर्श कर सकती हैं, जिनमें इलिनॉय आर्थिक विकास निगम, इच्छुक व्यवसाय और व्यावसायिक संगठन, श्रम प्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं;

VIII. यह कि अंतर-एजेंसी कार्य समूह, सूचना अधिसूचना जारी होने के 120 दिनों के भीतर, राज्यपाल कार्यालय को रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए उपयुक्त विधायी भाषा का कोई भी मसौदा प्रदान करे;

IX. यह कि आईसीसी, डीसीईओ और आवश्यकतानुसार अन्य राज्य एजेंसियां, राज्य की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन के नए और उभरते विषयों पर अनुसंधान और विकास केंद्रित चर्चा आयोजित करेंगे; ऐसे विषयों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर), अपग्रेड, खर्च किया गया ईंधन, परमाणु संयंत्रों के लिए जल उपयोग और प्रौद्योगिकियां, और अन्य आवश्यक समझे जाने वाले विषय शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

X. यह कि आईसीसी प्रभावित लोड-सर्विसिंग संस्थाओं और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन संगठनों/स्वतंत्र सिस्टम ऑपरेटरों (आरटीओ/आईएसओ) दोनों के साथ मिलकर काम करे ताकि किसी भी संभावित नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन परियोजना की ग्रिड से जुड़ने की क्षमता सुनिश्चित की जा सके और समय पर और आर्थिक रूप से लाभकारी इंटरकनेक्शन में बाधा डालने वाले किसी भी वित्तीय, तकनीकी या कानूनी मुद्दों का समाधान किया जा सके; इस तरह के सहयोग में आरटीओ/आईएसओ के साथ मिलकर इंटरकनेक्शन अध्ययन प्रक्रियाओं में सुधार करना शामिल

हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ताकि नए संसाधनों के तेजी से इंटरकनेक्शन को सुविधाजनक बनाया जा सके या आरटीओ द्वारा प्रस्तावित किसी भी त्वरित इंटरकनेक्शन मार्गों में नए परमाणु ऊर्जा उत्पादन की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

XI. यह कि डीसीईओ नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण और संचालन में सहयोग हेतु संभावित कार्यबल की आवश्यकताओं का आकलन करे और आवश्यक प्रशिक्षण संसाधनों में देखी गई किसी भी कमी को दूर करने के लिए योजना विकसित करे;

XII. यह कि डीसीईओ वित्त वर्ष 27 के बजट में परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण प्रशिक्षण अकादमी के लिए धन देने पर विचार करे; और

XIII. डीसीईओ को एक परमाणु ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें सितंबर 2026 तक विस्तार और विकास के लिए तैयार इलिनॉय की मौजूदा कंपनियों की पहचान की जाए। इस रिपोर्ट को तैयार करने में, डीसीईओ इलिनॉय विश्वविद्यालय प्रणाली, इलिनॉय आर्थिक विकास निगम, इलिनॉय विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र, इलिनॉय निर्माता संघ और आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य व्यावसायिक संघों के साथ सहयोग करेगा।

XIV. **संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़)।** इस कार्यकारी आदेश की कोई भी बात किसी भी संघीय या राज्य कानून अथवा विनियम का उल्लंघन करने के रूप में नहीं समझी जाएगी। इस कार्यकारी आदेश में कोई भी प्रावधान किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा।

XV. **विच्छेदनीयता** यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो यह अमान्यता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अमल को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अमान्य प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक करने योग्य घोषित किया जाता है।

XVI. **प्रभावी होने की तारीख** यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

_____
जे. बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 18 फरवरी, 2026
राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 18 फरवरी, 2026